भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1697
जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है।
8 श्रावण, 1947 (शक)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार सृजन

1697. श्री जिया उर रहमानः
श्री छोटेलालः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और छोटे शहरों की पृष्ठभूमि के युवाओं को डिजिटल कौशल, सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा से संबंधित अवसरों की सुलभता में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने और डिजिटल इंडिया, भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्लस्टर योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत में एक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है। यह 250 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 60 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। इसके अलावा, सरकार ने मार्च 2024 में इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस एआई रणनीति का उद्देश्य भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करना है। यह भारत के विकास लक्ष्यों के अनुरूप एक सुदृढ़ और समावेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल है। भारत एआई परियोजनाओं के लिए गिटहब का दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, जो इसके जीवंत डेवलपर समुदाय को प्रदर्शित करता है। स्टैनफोर्ड एआई रैंकिंग जैसी वैश्विक रैंकिंग, एआई कौशल, क्षमताओं और एआई के उपयोग की नीतियों में भारत को शीर्ष देशों में स्थान देती हैं।

फ्यूचर स्किल्स प्राइम: सरकार ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम के तहत 22.79 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों को नामांकित किया है । यह कार्यक्रम उद्योग संघ नैसकॉम के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को एआई, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, साइबर सुरक्षा आदि जैसी उभरती तकनीकों में कुशल बनाना है।

युवाई: यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई: स्कूली छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसका उद्देश्य कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को सक्षम बनाना है। यह 8 विषयगत क्षेत्रों - कृषि, आरोग्य,

शिक्षा, पर्यावरण , परिवहन , ग्रामीण विकास, स्मार्ट सिटी और विधि और न्याय में एआई कौशल पर केंद्रित है ।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी **एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट):** नाइलिट ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं के लिए डिजिटल कौशल और एआई, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती तकनीकों तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पिछले पाँच वर्षों में, नाइलिट ने अपने विभिन्न केंद्रों और कौशल विकास पहलों के माध्यम से 43.6 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया है।

स्टार्टअप और नवाचार के लिए सहयोग: एमईआईटीवाई के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं जैसे टाइड 2.0 (उद्यमियों का प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन और विकास), माईटी स्टार्टअप हब (एमएसएच), और उभरती प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता केंद्र देश भर में स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप, फंडिंग सहायता, इनक्यूबेशन और तकनीकी अवसंरचना तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा): देश भर में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमजीदिशा की शुरुआत की गई। 6 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष, देश भर में लगभग 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास: सरकार ने देश में ईएसडीएम क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास हेतु दो योजनाएँ लागू की हैं। दोनों योजनाओं के अंतर्गत, कुल 4,93,919 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है , 3,75,289 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है और कुल 1,38,275 उम्मीदवारों को रोजगार मिला है।

कौशल विकास में योगदान देने वाली अतिरिक्त पहलें:
i) स्किल इंडिया मिशन: कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत, इस मिशन में युवाओं के बीच रोजगार और उद्यमिता में सुधार के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में उद्योग की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

ii) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से अपस्किलिंग और रिस्किलिंग करना। इसके अलावा, यह योजना नए युग के उभरते पाठ्यक्रमों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा आदि पर भी केंद्रित है। पीएमकेवीवाई के तहत, अब तक कुल 25.77 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 15.39 लाख उम्मीदवारों को प्रमाणित किया जा चुका है।

iii) अटल नवाचार मिशन: नीति आयोग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एआईएम-राज्य साझेदारी शुरू की है।

*****